

संक्षिप्त समाचार

फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए केरल में छुट्टी

- आज बंद रहेंगे स्कूल,छात्रों की मांग पर सरकार का फैसला



तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने फीफा विश्व कप फाइनल के कारण सोमवार को राज्य के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। शिक्षा विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि यह निर्णय उन छात्रों के अनुरोध पर विचार करने के बाद लिया गया जो फुटबॉल के प्रशंसक हैं और रविवार रात होने वाला विश्व कप फाइनल देखना चाहते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अवकाश सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों पर लागू होगा। सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अवकाश की घोषणा की। मंत्री ने लिखा, ‘बच्चों अब खुश हो?’ उन्होंने कहा कि फुटबॉल प्रेमी छात्रों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए केरल सामान्य शिक्षा विभाग ने फीफा विश्व कप फाइनल के मद्देनजर सोमवार (20 जुलाई) को विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

वीआईपी रोड-बड़े तालाब में मिला युवक का शव

भोपाल (नप्र)। भोपाल के वीआईपी रोडस्थित बड़े तालाब में रविवार दोपहर 3 बजे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव को पानी में तैरता देखा और तलैया थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं होसकी है। गोताखोर शेख आसिफ ने बताया कि शव को पानी से बाहर निकालने के बाद तलाशी ली गई। युवक की जींस की जेब से एक मोबाइल फोन और वाहन की

चाबी मिली। मोबाइल पानी में रहने के कारण खराब हो चुका है। मृतक के पैरों में चप्पल नहीं थी, जिससे प्रारंभिक तौर पर तालाब में छलांग लगा देने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस मौत के सही कारणों की जांच कर रही है।

24 घंटे पुराना है शव

पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष है। उसने हल्के नीले रंग की जींस और धारीदार क्रीम रंग की शर्ट पहन रखी थी। शव करीब 24 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक तालाब में कब और कैसे पहुंचा। तलैया थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

मुंबई में राज ठाकरे के घर में घुसा बंदरों का झुंड

- भगाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के मुंबई स्थित आवास पर रविवार को बंदरों का एक झुंड घर के परिसर में घुस आया। अचानक बंदरों के घुस जाने से अफरातफरी का माहौल बन गया। घर के अंदर बंदरों को देख परिवार और स्टाफ के लोग घबरा गए। इसके बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम से संपर्क किया



और वन्यजीवों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए सहायता मांगी। मौके पर पहुंची टीम ने बंदरों को बिना किसी नुकसान के घर से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बंदरों का झुंड घर के अलग-अलग हिस्सों में घूमता रहा जिससे कुछ समय के लिए वहां अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि, इस घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। फिलहाल राज ठाकरे के घर पर बंदरों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का अभियान जारी है। मुंबई जैसे महानगर में रहियशी इलाकों में बंदरों के घुसने की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं।

गौरव अवस्त्री

राजघाट स्थित बापू की समाधि के निकट गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के सत्याग्रह मंडप में जब भी प्रभाष प्रसंग आयोजित होता है, वह केवल एक स्मृति-समारोह नहीं रह जाता; वह विचारों, मूल्यों और पत्रकारिता के आत्मबोध का उत्सव बन जाता है। इस वर्ष 12 जुलाई को आयोजित 16वें प्रभाष प्रसंग ने भी इसी परंपरा को नए अर्थ दिए। अवसर था हिन्दी पत्रकारिता की द्वि-शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रभाष परंपरा न्यास द्वारा प्रभाष जी की जयंती पर प्रकाशित दसवीं पुस्तक ‘पत्रकारिता का युगधर्म’ का लोकार्पण का।

यह पुस्तक केवल पृष्ठों का संकलन नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की उस नैतिक चेतना का दस्तावेज है, जिसे प्रभाष जोशी ने अपने लेखन से जिया। जनसत्ता, प्रथम प्रवक्ता और युगवार्ता में समय-समय पर प्रकाशित उनके 41 लेख इस ग्रंथ में संकलित हैं। इन लेखों में समाचारों की क्षणभंगुरता नहीं, बल्कि विचारों की दीर्घजीविता है; घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि पत्रकारिता का धर्म और उसका विवेक है। इस पुस्तक के पीछे प्रभाष जी के आत्मीय साथी और उनके सुयोग्य शिष्य पद्मभूषण रामबहादुर राय की प्रेरणा है, जबकि संपादन का दायित्व मनोज मिश्र ने निभाया है। यह उनका पौर्वांचल संपादकीय प्रयास है। विशेष रूप से ‘विनोबा दर्शन’ जैसी पुस्तक इस कड़ी को और अधिक मूल्यवान बना देती है। प्रभाष परंपरा न्यास ने प्रभाष जी के विस्तृत

पत्रकारीय जीवन में बिखरे विचार-मोतियों को जिस धैर्य और निष्ठा से एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है, वह केवल



प्रशंसनीय ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के प्रति एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भी है।

प्रभाष प्रसंग के माध्यम से प्रकाशित इन पुस्तकों में जनपक्ष केंद्र में हैं। जनसत्ता के संपादकीयों, अग्रलेखों और वैचारिक टिप्पणियों, प्रथम प्रवक्ता एवं युगवार्ता पत्रिका के लिए लिखे गए आलेखों में बिखरी हुई वह चेतना यहाँ एक सुसंगठित रूप में सामने आती है। इसलिए ये पुस्तकें केवल पत्रकारों या पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के

लिए उपयोगी हैं जो समाज, लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन की धड़कनों को समझना चाहता है। प्रभाष जोशी किसी एक पेशे या वर्ग के नहीं थे। वे अपने समय की सामूहिक चेतना के प्रहरी थे। जबलपुर के डकैतों के आत्मसमर्पण का प्रसंग हो या अयोध्या में विवादित ढोंवे के विच्छंस के बाद उनका ऐतिहासिक प्रतिरोध—प्रभाष जी ने हर बार शब्दों की गरिमा और मौन की शक्ति, दोनों का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत किया। हिन्दी पत्रकारिता में उनका वह ‘काला संपादकीय’ आज भी प्रतिरोध की सबसे सशक्त अभिव्यक्तियों में गिना जाता है। यद्यपि इस परंपरा का पहला उदाहरण 1931 में ‘भविष्य’ पत्रिका की संपादक लक्ष्मीदेवी ने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने सभी संपादकों के जेल भेजे जाने के विरोध में संपादन की बागडोर संभालकर संपादकीय स्तंभ रिक्त छोड़ दिया था; किंतु प्रभाष जी ने उस मौन को और अधिक तीक्ष्ण बनाते हुए पूरा संपादकीय स्तंभ काला कर दिया। वह मौन नहीं, समय के अंतःकरण की आवाज था। प्रभाष जोशी की पत्रकारिता किसी बाहरी दबाव या लोकप्रियता की आकांक्षा से संचालित नहीं होती थी। उसकी दिशा उनके भीतर अंकित नैतिक ‘लक्ष्मण रेखा’ तय करती थी। पाठकों के प्रति उनकी जवाबदेही उतनी ही गहरी थी, जितनी अपने अंतःकरण के प्रति। यही कारण है कि उनका लेखन आज भी विश्वास की तरह पढ़ा जाता है। प्रभाष परंपरा न्यास द्वारा अब तक प्रकाशित सभी पुस्तकें केवल

स्मृति-ग्रंथ नहीं, बल्कि अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जीवित दस्तावेज हैं। वे प्रभाष जी का पता तो देती ही हैं, साथ ही उस दौर के समाज की आत्मा से भी परिचय कराती हैं। मेरा अपना सौभाग्य है कि चितौड़ से लेकर दिल्ली तक आयोजित प्रभाष प्रसंग के अधिकांश आयोजनों का साक्षी बनने का अवसर मुझे मिला। हर बार लौटते हुए यही अनुभव हुआ कि स्मृतियाँ तभी जीवित रहती हैं, जब वे विचारों में बदल जाएँ। शायद यही कारण है कि प्रभाष प्रसंग देश और दिल्ली के उन विरल आयोजनों में है, जहाँ आचार और विचार साथ-साथ चलते हैं। यहाँ औपचारिकता नहीं, आत्मीयता है; प्रदर्शन नहीं, साधना है; और स्मरण नहीं, जीवन-मूल्यों का पुनर्संमरण है। सोलह वर्षों की इस सतत यात्रा में प्रभाष जी के संस्कारों की ऊष्मा, उनके स्वभाव की सहजता, लोकजीवन की सौधी गंध और भारतीय आत्मा की उदारता निरंतर अनुभव की जा सकती है।

इन आयोजनों का सबसे स्थायी पक्ष वे पुस्तकें हैं, जो हर वर्ष एक नई वैचारिक निधि के रूप में हमारे हाथों में आती हैं। कक्षा भी गया है-अक्षर अक्षर हैं। चित्रालिपियों से आरंभ हुई अक्षर-यात्रा आज डिजिटल संसार तक पहुँच चुकी है, पर पुस्तकें आज भी स्मृतियों और विचारों का सबसे विश्वसनीय आश्रय हैं। व्यक्ति नश्वर होता है, किंतु उसके विचार पुस्तक बनकर काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं।

जम्मू कश्मीर में ‘बादल फटे, ‘प्रलय’ की बारिश

11 लोगों की मौत, 2 साल के मासूम का शव निकाला



नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ और किरतवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए। बाढ़-लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। पुंछ के सुनकोट में



लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए। किरतवाड़ के सुनुं इलाके में बादल फटने से

मुख्यमंत्री ने अपना दौर छोटा किया

इसी बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि वह दिल्ली में अपना प्रवास छोटा कर रहे हैं और जमीनी स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए जम्मू लौट रहे हैं। अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम चेतावनी और जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं आज दोपहर दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरूंगा, ताकि व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्थिति का जायजा ले सकूँ।

एलजी ने स्थिति की समीक्षा की

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारिश और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित पुंछ और राजौरी जिलों में स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रशासन, पुलिस, सेना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय स्वयंसेवकों की बचाव टीमें मौके पर काम कर रही हैं, जबकि सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए सिन्हा ने पुंछ के हवेली और सुनकोट इलाकों में हुई मौतों पर गहरा दुख जताया और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता का आश्वासन दिया।

बंगाल में पुलिस की वर्दी में चोरी हुई, मेरा ऑफिस तोड़ा

अभिषेक बोले-बीजेपी के गुंडे सामान उठा ले गए, कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाई

कोलकाता (एजेंसी)। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पश्चिम बंगाल पुलिस खुद कानून तोड़ने वाली बन गई है। यह बयान उन्होंने दक्षिण 24 परगना के अमरतला स्थित अपने ऑफिस को तोड़े जाने के एक दिन बाद दिया। शनिवार को जिला प्रशासन ने इमारत का अगला हिस्सा बुलडोजर से गिरा दिया था। आरोप था कि यह बिना मंजूरी के बना था। हालांकि रविवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस तोड़-फोड़ पर रोक लगा दी है। साथ ही इसे अगली सुनवाई तक ज्यों का त्यों रखने का आदेश



दिया है। इससे पहले इमारत तोड़ने के बाद रात का एक वीडियो अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। अभिषेक ने आरोप लगाया- बंगाल पुलिस बीजेपी के गुंडों के साथ मिलकर लैपटॉप, प्रिंटर, कागजात, टेबल, कुर्सियां और दूसरे फर्नीचर से भरे बक्से ले जा रही है।

राममंदिर चढ़ावा चोरी पर राहुल ने मोदी को लिखी चिट्ठी

कहा-आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं, ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक हों

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। खातों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि हर भक्त जान सके कि चढ़ावे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे हुआ। जांच में जो भी जिम्मेदार पाए जाएं, उनकी जवाबदेही तय हो। शनिवार को लिखी चिट्ठी रविवार को सामने आई। उन्होंने पीएम मोदी से कहा-आपने संसद में ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार ने की। यह बात जगजाहिर है कि ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, वीएचपी और उसके सहयोगियों से जुड़े हैं। पूर्व महासचिव भी आपके करीबी थे। ऐसे में आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं है। जवाबदेही सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है। सरकार और ट्रस्ट की साख इसी बात पर टिकी है। इधर, आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नु और उसके



भतीजे मनोष की पुलिस कस्टडी का आज आखिरी दिन है। शनिवार सुबह साढ़े 8 बजे पुलिस दोनों को जिला जेल से अपने साथ 39 घंटे की रिमांड पर ले गई थी। पुलिसकर्मी रात 11 बजे तक अपने ऑफिस में ही मौजूद रहे। आरोपियों को कहीं और नहीं ले जाया गया। टिन्नु, पूर्व महासचिव चंपत राय का करीबी रहा है। वह मंदिर के दानपात्रों की देखरेख करता था, जबकि मनोष चढ़ावे की गिनती का काम करता था।

संघ और विहिप ने 23 जुलाई को संतों का सम्मेलन बुलाया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 23 जुलाई को अयोध्या की मणिराम छवनी में संतों का सम्मेलन बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक, आरएसएस के स्वयंसेवक और वीएचपी के कार्यकर्ता श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। संभल में शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन औवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोला।

दतिया उपचुनाव

जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लगाया गले, एक दिन पहले कहा था कि पहली बार सुना हूं नाम



दतिया (नप्र)। मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। दतिया से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सामान बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से हुआ है। जीतू पटवारी ने आशुतोष तिवारी को गले लगा लिया। इस दौरान दोनों मुस्कुराते नजर आए हैं। **आशुतोष तिवारी पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव-** दरअसल, दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से आशुतोष तिवारी लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ही उनका सामान आशुतोष तिवारी से हुआ। इस दौरान जीतू पटवारी ने उन्हें मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।



अलर्ट पर रखे गए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका के 50,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं। तनाव को देखते हुए सभी सैनिक अलर्ट मोड पर हैं और आगे की किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमेरिका अरब में सैनिकों के अलावा अपने फाइटर जेट की मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसके लिए

इजरायल की

घटनाक्रम पर नजर

यरुशलम पोस्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर इजरायल बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिकी सेना लगातार आठ रातों के हमलों के बाद नौवें दिन भी ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि फिलहाल ईरान ने उनके देश पर हमले से परहेज किया है लेकिन आने वाले दिनों में चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने फिलहाल इजरायल से लड़ाई से दूर रहने के लिए कहा है। इजरायल ने कथित तौर पर ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की पेशकश की थी लेकिन वॉशिंगटन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

वनभूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला, सरकारी वाहन तोड़े

इंदौर। चोरल रेंज के रसकुंडिया वन क्षेत्र में शासकीय वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर शनिवार को हिंसक हमला किया गया। कार्रवाई का विरोध कर रहे अतिक्रमणकारियों ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया और वन विभाग की दो जेसीबी मशीनों, एक शासकीय वाहन तथा एंबुलेंस में जमकर तोड़फोड़ की। हालात ऐसे बन गए कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर तलवार, फालिया और अन्य धारदार हथियार लेकर वन कर्मियों के पीछे दौड़े। इस दौरान वनरक्षक आनंद सिंह चायल हो गए। घटना में विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चोटें आने की जानकारी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।



चोरल के रसकुंडिया वन क्षेत्र में हिंसा, हथियार से वनरक्षक पर हमला

हमलावरों की पहचान हो रही

घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वन विभाग और पुलिस ने हमले में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई इस हिंसक घटना ने सरकारी अमले की सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील कार्रवाई के दौरान अपनाई जाने वाली तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम की व्यापक चर्चा हो रही है।

माहौल हिंसक हो गया

जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम शासकीय वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और माहौल हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने जेसीबी मशीनों, शासकीय वाहन और एंबुलेंस को निशाना बनाते हुए भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। सूत्रों का कहना है कि घटना के समय रेंज के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। यह भी चर्चा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक संसाधनों का अभाव था। वहीं पुलिस के देर से मौके पर पहुंचने की बात भी सामने आ रही है, हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।



मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह करें। इसके बाद सांसद लालवानी ने मौके पर ही स्पीकर फोन के माध्यम से पुलिस कमिश्नर से बात की और परिजनों की भी उनसे बातचीत करवाई। बातचीत के दौरान पुलिस कमिश्नर ने इस हत्याकांड को अत्यंत नृशंस बताते हुए कहा कि यह घटना शहर के माथे पर कलंक है। उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस की टीम भेजी गई है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजनों ने सांसद के समक्ष यह भी कहा कि अन्य चर्चित मामलों में जांच एजेंसियां और प्रशासन तत्काल सक्रिय हो जाते हैं

तथा विशेष जांच दल का गठन भी किया जाता है, लेकिन इस मामले में 14 वर्ष से विवाहित और दो छोटे बच्चों के पिता द्वारा अपनी पत्नी की कथित निर्मम हत्या के बावजूद अपेक्षित स्तर पर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने इस मामले में भी एसआईटी गठित कर निष्पक्ष और तेज जांच कराने की मांग दोहराई। सांसद शंकर लालवानी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि वे शनिवार रात ही इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए जाने का आग्रह करेंगे।

आपसी रंजिश के चलते घर पर हमला

इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक के घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना शुक्रवार रात विजयश्री कॉलोनी कालानी नगर के पास की है। यहां रहने वाले राहुल राठौर के घर पर पप्पू खटिक अपने साथियों के साथ पहुंचा और घर पर पथराव करते हुए तोड़फोड़ की। अचानक हुए हमले से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी घर पर पथराव और नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। एसीपी अशोक सिंह जादौन ने बताया कि राहुल राठौर और पप्पू खटिक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हमला किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। यदि जांच में किसी हथियार के इस्तेमाल की पुष्टि होती है, तो उसे जब्त कर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।

चंदन नगर थाना चौथी बार शहर में अटवल

इंदौर। शहर के सभी थानों के कार्यों की पुलिस कमिश्नर स्तर पर रैंकिंग तय की जाती है। इसमें जो भी थाना बेहतर परफॉर्मेंस करता है, उससे नंबर वन का खिताब दिया जाता है। जून माह के मूल्यांकन में एक बार फिर चंदन नगर थाने ने नंबर वन स्थान पाया। वह चौथी बार अटवल रहा। थानों के कार्यों की समीक्षा संबंधित जौन की डीसीपी की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा तय मापदंडों पर की गई। इसके आधार पर सभी 32 थानों के कार्य निष्पादन, जनसंतुष्टि और आमजन के हित में किए जा रहे नवाचारों आदि पैरामीटर के आधार पर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए थाना चंदन नगर प्रथम स्थान रहा, जबकि बाणगंगा ने द्वितीय और द्वारकापुरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले थाने के थाना प्रभारी सहित स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं कमजोर परफॉर्मेंस वाले थाने के टीआई और स्टाफ को और बेहतर कार्रवाई के लिए आवश्यक ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। बता दें, पुलिस कमिश्नरेंट द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर, अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुखी बनाए जाने के प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

पत्नी को घर ले जाने पहुंचे पति की हत्या

इंदौर। बड़गाँदा थाना क्षेत्र स्थित निसर्ग फार्म हाउस में पत्नी को वापस घर ले जाने पहुंचे 45 वर्षीय राजू बामनिया की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ है। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने आरोपी संतोष पिता शंकर चौहान, निवासी छापरी (राजेंद्र नगर) के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, राजू अपनी पत्नी आरती को घर ले जाने फार्म हाउस पहुंचा था, जहां वह संतोष के साथ रह रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि गुर्रसे में संतोष ने लोहे की टामी से राजू के सिर, कनपटी और आंख के नीचे ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण राजू की मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार

इंदौर। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने देर रात चेकिंग अभियान के दौरान एक शांतिर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.30 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार एमआर – 4 रोड पर संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान मयूर पिता संभाजी तांबारे, निवासी बंसी प्रेस की वाल, परदेशीपुरा के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे नशे के नेटवर्क और सप्लायरों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

अपराधियों पर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, सात बदमाश जिलाबदर किए

तीन हत्या, तीन प्रयास के आरोपी सादिक गुलफाम समेत 10 पर शिकंजा



गतिविधियां बंद नहीं हुई और वे लगातार क्षेत्र की शांति तथा कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे।

जिला बदर के आदेश जारी – पुलिस कमिश्नर ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सादिक गुलफाम, मोहम्मद अयाज, फैजल

उर्फ कालू शाह, फारुख उर्फ लंबू, कारण उर्फ कन्नू, गणेश परमार उर्फ पटेल तथा किशोर उर्फ कुणाल को निर्धारित अवधि के लिए इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण और सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। आदेश प्रभावी रहने

तक इन बदमाशों का संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

तीनों को थाने में हजिरी जरूरी

इसके अतिरिक्त मनीष उर्फ चिकना, लोकेश चौहान और नीलेश पवार पर निर्बंधन आदेश जारी किए गए हैं। इन तीनों को तय अवधि तक संबंधित थाने में नियमित हजिरी दर्ज करानी होगी। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होने और लोक शांति भंग करने वाले कृत्यों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित बदमाशों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध इसी तरह प्रभावी कदम उठाए जाते रहेंगे।

महिला एसआई के भाई पर हेड कांस्टेबल से मारपीट का आरोप

तेज हॉर्न बजाने पर हुआ विवाद, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस

प्रधान आरक्षक ने चालक को शांत रहने और अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाने की समझाइश दी। आरोप है कि इस बात से नाराज चालक ने कार का शीशा नीचे किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा।

धक्का-मुक्की का आरोप- पुलिस के अनुसार, विवाद बढ़ने पर आरोपी कार से नीचे उतरा और प्रधान आरक्षक की बाइक की चाबी छीनकर ले जाने लगा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। जांच में आरोपी की पहचान अनुराग तिवारी के रूप में हुई है, जो महिला थाना में पदस्थ एसएसआई का भाई बताया जा रहा है।

पुलिस ने अनुराग के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

मजिस्ट्रेट पति के होने की चर्चा- पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के समय अनुराग तिवारी के साथ कौन था। उसकी भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है और अब तक उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अनुराग तिवारी शराब के नशे में था। मेडिकल परीक्षण के बाद उसके खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत भी कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है।

110 कारें और 100 मोटरसाइकिल से इंदौर से मांडव तक नशा मुक्ति रैली

750 युवाओं ने दिया नशे के खिलाफ जन जागरण का संदेश



साइक्लोटॉन का आयोजन

इससे पहले नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में साइक्लोटॉन का आयोजन किया गया। रन फॉर ए हेल्दी लाइफ, सेय नो टू ड्रम्स थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में 400 साइक्लिस्ट शामिल हुए। साइक्लिस्ट ने शहरवासियों को स्वस्थ एवं नशा मुक्ति जीवन अपनाने का संदेश दिया। इसमें बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बीएसएफ के जवानों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। खास बात यह रही कि छोटे बच्चों से लेकर 70 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों ने भी साइकिल चलाकर नशे के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई।

दुष्परिणामों से अवगत कराया। मार्ग में मौजूद लोगों ने भी इस जनजागरूकता अभियान का स्वागत करते हुए इसे समाज के लिए सकारात्मक पहल बताया। इंदौर पुलिस का 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान लगातार जनसहभागिता के साथ आगे बढ़

रहा है। अभियान का उद्देश्य केवल नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना ही नहीं, बल्कि युवाओं, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों की सहभागिता से नशामुक्त, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करना भी है।



संपादकीय

अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी !

निजी क्षेत्र में विकसित भारत का पहले ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ ने कई टेक्नोलॉजी डेमोनेस्ट्रेशन पेलोड और पोस्टकार्ड्स को लो अर्थ ऑर्बिट को स्थापित कर देश को नई उपलब्धि दिलाई है। इस सफलता से पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ‘विक्रम-1’ अपने जो पोस्टकार्ड ले गया है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट कार्ड भी है। निजी क्षेत्र का यह पहला रॉकेट निजी कंपनी हैदराबाद की स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित है, जिसे इसरो ने अपने लांच पैड से लांच किया। रॉकेट चार साल पहले इसी कंपनी ने विक्रम-एस नामक एक सबऑर्बिटल रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी के सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना के अनुसार इस लांचिंग को ‘मिशन आगमन-1’ नाम दिया गया है। यह भारत का पहला कमर्शियल लॉन्च व्हीकल है। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम-1 रखा गया है। विक्रम-1 सैटेलाइट को ‘लो अर्थ ऑर्बिट’ में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छोटे साइज के सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। दावा है कि यह सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इस रॉकेट का वजन 40 टन है और यह 20 मीटर यानी लगभग सात मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। इसकी क्षमता 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सैटेलाइट ले जाने की है। विक्रम-1 के जरिए छह तरह के पेलोड चांद पर भेजे जा रहे हैं। स्काईरूट ने घोषणा की है कि विक्रम-1 के लॉन्च के बाद विक्रम-2 का लॉन्च किया जाएगा। इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। विक्रम-1 की तरह ही इसमें कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा और एडवांस क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने 2019 में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर (इन्-स्पेस) की स्थापना के साथ स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था। यह संस्था प्राइवेट सेक्टर और इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों के बीच एक सिंगल-विंडो इंटरफेस के रूप में काम करती है। विक्रम 1 की कामयाब लांचिंग के बाद निजी क्षेत्र में उग्रहर्षण को लांच करने का नया क्षेत्र खुलेगा। इससे इसरो को भी आय होगी, क्योंकि लांचिंग पैड उसी के पास हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सफलता के बाद भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक नए और महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गया है। एक तरफ अंतरिक्ष में हमारे निजी स्टार्ट अप की यह सफलता है तो दूसरी तरफ चिंता की बात ‘भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन’ यानी इसरो से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का तेजी से नौकरा हो खंडना है। हालांकि सरकार ने एक आदेश जारी कर वैज्ञानिकों के इस्तीफे मंजूर करने पर रोक लगा दी है, लेकिन यह दबाव बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। क्योंकि नौकरी छोड़ने के इच्छुक वैज्ञानिकों को जबरन रोका गया तो उनके मन में कुटुंभ और निराशा फैल सकती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के इससे छोड़ने के पीछे कारण निजी स्टार्ट अप्स में बेहतर वेतन और काम करने के अवसर हैं। बताया जाता है कि पिछले एक साल में अनुमानित 100-120 वैज्ञानिक इसरो छोड़कर स्पेस स्टार्टअप से जुड़ गए हैं, जहां वह मनमाना काम कर सकते हैं। इसरो भी कितना ही बड़ा और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान क्यों न हो, लेकिन कामकाज की सरकारी रफ्तारथर से वह भी अट्ठ्ठा नहीं है। लिहाजा सरकार को भी अपनी वैज्ञानिकों की सेवा शर्तों और प्रतिभा उपयोग के अपने पारंपरिक मानदंडों पर पुनर्विचार करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। अन्यथा इसरो जैसी देश की गौरवपूर्ण संस्था प्रतिभाओं से खाली होने में देर नहीं लेगी। ऐसा हुआ तो यह राष्ट्रीय हानि होगी। यह कहीं से भी देशहित में नहीं होगा।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।



रघु धर्षि दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में नये-नये प्रकार की खोजें हुईं और प्रतिदिन हो रही हैं। ऐसी बीमारियां जो सदियों से लाइलाज मानी जाती थीं, उनका भी इलाज और दवाइयाँ खोजी गईं। 17-18 वीं सदी में प्रतिवर्ष लाखों लोग देश में हैजा, टीबी जैसी बीमारियों से मौत के शिकार होते थे, परंतु अब इनसे होने वाली मौतें बहुत कम हो गयीं। 19वीं सदी में देश में हैजा से मरने वालों की संख्या लाखों में थी परंतु अब इनकी वैक्सीन के आने से इनसे होने वाली बीमारियों से मृत्युदर भी कम हुई। हालांकि दूसरी तरफ कैंसर जैसी नयी-नयी बीमारियाँ का उदय हुआ है जिससे मरने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। कैंसर का फैलाव भी पिछले दो दशकों में काफी हुआ है। और लाखों लोग कैंसर के शिकार हैं। कैंसर के इस फैलाव की वजह पर कुछ कह पाना निश्चित नहीं है। परंतु विशेषज्ञों का कहना है कि देश में बढ़ता प्रदूषण, धूल और धुआँ, पानी, वायु और खाद्यान्न में दवाईयों के नाम पर शुलता जहर इसका बड़ा कारण है। पिछले तीन चार दशकों में देश में बड़े-बड़े अस्पताल खुले हैं। फाइव स्टार संस्कृति के निजी अस्पतालों का भी भारी फैलाव हुआ है, परंतु देश का आम आदमी अभी भी चिकित्सा के अभाव में जी रहा है। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना बनाई परंतु उसमें केवल बड़ी बीमारियाँ ही शामिल की गईं और इसका लाभ सामान्य व्यक्तियों और आमजन के लिये यह योजना सरकारों के संरक्षण में भ्रष्टाचार का शिकार हो गयी। पिछले दिनों यह खबर अखबारों में आयी थी कि सैकड़ों करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार आयुष्मान योजना में हुआ है। बहुतेरे अस्पतालों के सदिग्ध बिल सरकारों ने रोक दिये और अब स्थिति यह है कि अधिकांश अस्पताल आयुष्मान कार्ड मानने को तैयार नहीं हैं।

देश में लगभग 8-10 करोड़ लोग जिनमें केंद्र और राज्य के अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक, निजी कंपनियों के कर्मचारी, व्यापार में संलग्न लोग आदि शामिल हैं। जिनके पास किसी न किसी प्रकार का चिकित्सा बीमा है या सरकार के स्तर से चिकित्सा की सुविधाएँ हैं। जो अति गरीब लोग हैं उन्हें भी सरकार की ओर से इलाज मुफ्त मिलता है यद्यपि वह सामान्य बीमारियों तक ही ज्यादा होता है। परंतु देश का एक निम्न और सामान्य मध्यवर्ग जिसमें छोटे किसान,

चिकित्सा मूल अधिकार बने

छोटे कर्मचारी, छोटे व्यापारी जैसे लोग हैं और जिनकी संख्या 60 करोड़ से कम नहीं होगी, ये लोग आज भी छोटी या बड़ी बीमारी के इलाज के लिए सरकार की सूची से बाहर हैं। इनमें बीमा कराने की क्षमता भी नहीं है, कोई गंभीर बीमारी के आने पर अपनी अचल संपत्ति को बेचकर या कर्ज लेकर इलाज कराने को लाचार हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने पिछले लगभग 3 दशकों से यह मांग की है, (धरना, प्रदर्शन, सभा ज्ञापन आदि के माध्यम से) तथा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि चिकित्सा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए ताकि सभी को जरूरत के अनुसार चिकित्सा और दवा उपलब्ध हो सके तथा



चिकित्सा क्षेत्र का निजीकरण समाप्त कर समाजीकरण करना चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा देना किसी भी सरकार का मौलिक और संवैधानिक दायित्व है। जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनींं थीं तब उन्होंने हमारे ज्ञापन को गंभीरता से लेकर पहल शुरू की थी। बात काफी आगे तक बढ़ी भी परंतु उनका समय समाप्त होने के बाद यह प्रस्ताव फाइलों में बंद होकर मौत का शिकार हो गया।

अब देश में जो बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हैं निसंदेह पिछले 2 दशकों में उनकी संख्या बढ़ी है, पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या भी काफी बढ़ी है, परंतु इसमें दो प्रकार की समस्यायें हैंरू-

1. अब जो नये चिकित्सा महाविद्यालय पिछले 4-5 वर्षों में खोले जा रहे हैं वे सब पीपीपी मॉडल जिसका वास्तविक अर्थ प्रछन्न निजीकरण होता है, के आधार पर खोले जा रहे हैं और इनमें सामान्य व्यक्तियों के लिए इलाज कराना लगभग असंभव जैसा होता है। इनका लाभ भी संपन्न और बड़े लोग ही ले पाते हैं। गरीब तबका तो इससे वंचित ही रह जाता है। जाहिर

सी बात है कि जब कोई पूंजीपति अपना पैसा किसी क्षेत्र में लगायेगा वह घोषित या अघोषित रूप से मुनाफे के लिए ही लगायेगा और उससे आमजन को लाभ नहीं होगा।

2. जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी संख्या अवश्य बढ़ी है परंतु, क्या वह बढ़ी हुई आबादी की तुलना में पर्याप्त हैं? इस पर विचार करना चाहिए। देश की आबादी बढ़कर अब 150 करोड़ के आसपास है और आज भी देश की राजधानी में जो सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल जिसे एम्स कहा जाता है, की चिकित्सा की क्षमता क्या है? आपरेशनों के लिए 4-4, 5-5 साल का समय दिया जा रहा है, कई बार ऐसा होता है

कि गरीब का नंबर एम्स में नहीं लग पाता और यमराज के यहां लग जाता है। अभी हमारे एक परिचित जो किसी व्यक्ति को जलने से बचाने के उपक्रम (प्रयास) में स्वतः जल गये थे, दिल्ली के सफदरागंज अस्पताल में बर्न यूनिट में एयरलिफ्ट कर लाये गये थे। स्थिति यह थी कि उन्हें भर्ती करने के लिये बिस्तर भी खाली नहीं था और कुछ विशिष्ट प्रयासों के बाद उन्हें एक बेड मिल सका और जनरल वार्ड में भर्ती हो सके। उसमें अस्पताल के प्रबंधन या चिकित्सकों की कोई गलती नहीं है क्योंकि प्रतिदिन देशभर में जलने वाले मरीजों की संख्या सैकड़ों में है और उनके बर्न यूनिट की संख्या मुश्किल से 100 के आसपास है। यही स्थिति राजधानी के अन्य सरकारी अस्पतालों की है। जब दिल्ली में एम्स शुरू हुआ था तब दिल्ली शहर की आबादी 40 लाख और देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। यही स्थिति राज्यों के एम्स (सिम्स) और सरकारी चिकित्सालयों की है। परंतु सरकार की नीतियों में आबादी नियंत्रण नहीं है बल्कि अब तो आबादी बढ़ना है। आबादी बढ़ाने के अनेकों

प्रयास सरकारों कर रही हैं, तीसरे चौथे बच्चों के जन्म लेने पर कुछ प्रोत्साहन राशि स्वरूप देना तथा महिला के साथ-साथ पुरुष को भी बच्चे पालने का अवकाश आदि सुविधाओं की घोषणा हो रही है परंतु, चिकित्सालयों में आबादी और जरूरत के अनुसार सुविधायें बढ़ाना भी सरकार की नीति नहीं है। एम्स में सांसदों, विधायकों, अफसरशाहों के लिए पृथक व्यवस्था है और इन्हें तत्काल जरूरत के अनुसार पर्याप्त आवश्यक इलाज मिल जाता है। सेना के लिए सैनिक अस्पताल हैं। कई अन्य सरकारी विभागों के अपने अपने अस्पताल हैं या उनके बड़े अस्पतालों से अपने कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए समझौते हैं। पब्लिक सेक्टर में अधिकांश ने अपने कर्मचारियों के लिए बढ़िया अस्पताल सरकारी धन से बनाये हैं परंतु देश के आम आदमी के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। जनप्रतिधियों की प्राथमिकतायें भी अब आम आदमी नहीं हैं बल्कि संसद और विधानसभाओं का अधिकांश समय गैर जरूरी मुद्दों और बहस पर जाता है। मेरे पढ़ने में कम से कम पिछले 3-4 दशकों में यह कभी नहीं आया कि किन्हीं सांसद महोदय ने लोकसभा में देश के इन आम और गरीबों की बात को उठाया हो। किसी ने पूछा हो कि देश के आम आदमी के लिए एम्स में 5-7 साल की तारीख ऑपरेशन के लिए क्यों दी जाती है? किसी ने पूछा हो कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक बिस्तर पर 2-2 मरीज क्यों हैं? मरीज को ले जाने वाली ट्रालियों पर 5-5 मरीज क्यों ले जा रहे हैं। इंसान यानि मरीज और उसके परिजन अस्पतालों में और उसके बाहर खुले मैदानों में रातभर जानवरों के समान पड़े रहते हैं। इन बड़े चिकित्सालयों में मरीजों के परिजनों के लिए कमरा तो दूर एक दरी बिछाकर सोने लायक जगह भी योजनाओं में नहीं है।

हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि-
1. चिकित्सा का मूल अधिकार बनाया जाये और सारी चिकित्सा सरकारी हो।
2. व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार चिकित्सा और दवायें उपलब्ध हो।
3. आबादी के नियंत्रण के लिए कार्यवाही हो।
4. बढ़ती आबादी और उसकी जरूरतों के अनुसार चिकित्सालयों की क्षमता बढ़ाई जाये।
5. सरकारी चिकित्सालयों की निर्माण योजना में मरीजों के परिजनों के लिए चिकित्सालय के प्रांगण में विश्रामस्थल बनाना अनिवार्य हो।

दृष्टिकोण

निलेश देसाई

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।



गांधी, लोकतंत्र और हमारे समय का सबसे कठिन प्रश्न महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को कभी आंदोलन की तकनीक नहीं माना। उनके लिए सत्याग्रह सत्य की खोज, आत्मबल की अभिव्यक्ति और लोकतंत्र की नैतिक चेतना को जागृत करने का माध्यम था। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति बिना धृणा, बिना हिंसा और बिना प्रतिशोध के अन्याय का सामना करते हुए स्वयं कष्ट सहता है, तो वह केवल शाक्त से नहीं, बल्कि पूरे समाज की अंतरात्मा से संवाद करता है। सत्याग्रह का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को पराजित करना नहीं, बल्कि उसके भीतर सोई हुई नैतिक संवेदना को जगाना है।

यही कारण है कि सत्याग्रह केवल सत्याग्रही के साहस पर निर्भर नहीं करता। उसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज, मीडिया और शासन उस पीड़ा को देखने, समझने और उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि सुनने की यह क्षमता कमजोर पड़ जाए, तो सत्याग्रह का नैतिक प्रभाव भी क्षीण होने लगता है।

आज भारत के लोकतंत्र के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा है। हाल के वर्षों में शिक्षा, पर्यावरण, कृषि, रोजगार, भूमि अधिकार और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे अनेक मुद्दों पर शांतिपूर्ण धरने, पदयात्राएँ और अनशन हुए हैं। इनमें से कुछ को व्यापक समर्थन मिला, कुछ को सीमित ध्यान मिला और कुछ लगभग सार्वजनिक विमर्श से बाहर रह गए। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा आंदोलन सफल हुआ और कौन-सा नहीं, बल्कि यह है कि क्या आज भी अहिंसक प्रतिरोध लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है?

यह प्रश्न केवल किसी एक आंदोलन या सरकार का नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास का शायद सबसे बड़ा अहिंसक जनांदोलन था। गांधी ने यह स्थापित किया कि जनता की नैतिक शक्ति किसी भी साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति से बड़ी हो सकती है। स्वतंत्रता के बाद

असहमति से नफ़रत तक: लोकतंत्र की नैतिक परीक्षा

विश्व इतिहास का शायद सबसे बड़ा अहिंसक जनांदोलन था । गांधी ने यह स्थापित किया कि जनता की नैतिक शक्ति किसी भी साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति से बड़ी हो सकती है । स्वतंत्रता के बाद भी इसी परंपरा ने भूदान आंदोलन, चिपको, सूचना के अधिकार, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जनलोकपाल आंदोलन और अनेक स्थानीय जनसंघर्षों को दिशा दी । इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया; बल्कि उसे अधिक उत्तरदायी बनाया । इतिहास यह भी बताता है कि सत्ता और जनआंदोलनों के बीच तनाव हमेशा रहा है । औपनिवेशिक शासन ने गांधी और लोकमान्य तिलक पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए । स्वतंत्र भारत में भी अलग-अलग विचारधाराओं की सरकारों ने विभिन्न आंदोलनों को संदेह की दृष्टि से देखा । इसलिए यह प्रश्न किसी एक दल या एक सरकार तक सीमित नहीं है ।

भी इसी परंपरा ने भूदान आंदोलन, चिपको, सूचना के अधिकार, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जनलोकपाल आंदोलन और अनेक स्थानीय जनसंघर्षों को दिशा दी। इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया; बल्कि उसे अधिक उत्तरदायी बनाया।

इतिहास यह भी बताता है कि सत्ता और जनआंदोलनों के बीच तनाव हमेशा रहा है। औपनिवेशिक शासन ने गांधी और लोकमान्य तिलक पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए। स्वतंत्र भारत में भी अलग-अलग विचारधाराओं की सरकारों ने विभिन्न आंदोलनों को संदेह की दृष्टि से देखा। इसलिए यह प्रश्न किसी एक दल या एक सरकार तक सीमित नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक संस्कृति का प्रश्न है जिसमें असहमति को सम्मानपूर्वक सुनना धीरे-धीरे कठिन होता जा रहा है।

डिजिटल युग ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। आज सूचना पहले पहुंचती है और समझ बाद में बनती है। सोशल मीडिया ने नागरिकों को अभिव्यक्ति का अभूतपूर्व अवसर दिया है, लेकिन उसी के साथ समाज वैचारिक खोमों में भी बँट गया है। किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन उसके तर्कों से पहले उसकी राजनीतिक पहचान के आधार पर होने लगता है। परिणामस्वरूप संवाद सिक्कड़ता है और आरोप-प्रत्यारोप उसका स्थान ले लेते हैं।

लोकतंत्र में असहमति होना स्वाभाविक है। हर आंदोलन सही हो, यह आवश्यक नहीं। हर मांग स्वीकार हो, यह भी

संभव नहीं। लेकिन किसी भी लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से मापी जाती है कि वह असहमति का उत्तर किस प्रकार देता है। क्या वह संवाद करता है? क्या वह तथ्यों के आधार पर बहस करता है? या फिर वह विरोध करने वाले की नीयत पर ही प्रश्नचिह्न लगा देता है?



गांधी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने यह विश्वास पैदा किया कि बिना हिंसा के भी अन्याय का प्रतिरोध किया जा सकता है और परिवर्तन संभव है। यदि यह विश्वास कमजोर पड़ने लगे कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं रह गया है, तो इसका असर केवल आंदोलनों पर नहीं पड़ेगा; यह लोकतंत्र की बुनियाद को प्रभावित करेगा।

ऐसी स्थिति में समाज सामान्यतः तीन दिशाओं में बढ़ता है। पहली दिशा है उग्रता। जब लोगों को लगता है कि

शांतिपूर्ण मार्ग से कुछ नहीं बदलता, तब कुछ लोग हिंसक या कट्टर रास्तों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं।

दूसरी दिशा है उदासीनता। लोग यह मान लेते हैं कि उनकी आवाज का कोई महत्व नहीं है। वे सार्वजनिक जीवन से दूरी बना लेते हैं। यह मौन लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक है जितनी हिंसा, क्योंकि इससे जवाबदेही की संस्कृति कमजोर होती है।

तीसरी दिशा आशा की है। प्रत्येक पीढ़ी अपने समय के अनुरूप प्रतिरोध के नए माध्यम खोजती है। गांधी के समय चरखा, नमक यात्रा और पदयात्राएँ प्रतीक बने थे। आज डिजिटल अभियान, नागरिक नेटवर्क, सामुदायिक संवाद, जनसुनवाई और सोशल मीडिया नए माध्यम बन रहे हैं। अहिंसा समाप्त नहीं होती; वह अपने स्वरूप बदलती है। किंतु उसका नैतिक आधार वही रहता है-सत्य, आत्मानुशासन और संवाद।

यहीं लोकतंत्र की असली परीक्षा आरंभ होती है। क्या हमारी संसद, हमारी सरकारें, हमारा मीडिया और हमारा नागरिक समाज ऐसी आवाजों को सुनने की संवेदनशीलता बनाए रख पाए हैं? क्या हम असहमति को लोकतंत्र का स्वाभाविक अंग मानते हैं या उसे संकट के रूप में देखने लगे हैं?

सत्याग्रह का अर्थ केवल विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नैतिक परीक्षा भी है। जब कोई नागरिक बिना हिंसा के

मजे की बात है कि शरीफों की इकलौती पूंजी भी चुरा ली गई

के यहाँ चोरी होने को मनोरंजन की तरह लिया जाता था। लोग बस चोर को,उसकी दिलेरी और चोरी करने के तरीके की,चोरी गए माल की और जिसके यहाँ चोरी हुई है उसकी बदकिस्मती की चर्चा करते थे और तब तक करते थे जब तक अगली चोरी की खबर न आ जाए।

उन दिनों चोरी कोई ज्यादा फायदे का धंधा था भी नहीं। किसी के यहाँ संध लगाने की कड़ी मेहनत के बाद चोरी करने वाले के हाथ लगता क्या था? आमतौर पर कुछ गहने पैसे बरतन बस। वो इतनी छोटी सी चीजों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था। पकड़े जाने पर पिटाता था, पुलिस के हाथों अपनी जमा पूंजी गँवाता था और जेल जाता था। कहने का आशय यह कि पुराने जमाने में चोर होना खुद को खतरे में डालने जैसा था। चोर नाम और



दाम दोनों से हाथ धो बैठता था पर शूक्र है अब ऐसा नहीं है। एक सुखद बदलाव आ चुका हमारे यहाँ। चोरी के आयाम अब व्यापक हो चुके। धर्म राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी व्यापार जिंदगी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ चोरी करने की गुंजाइश न हो। लोग समझ गए है कि चोर होने में नुकसान जैसा कुछ नहीं। इसमें धन है,रोमांच है, शोहरत है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। शरीफों के

पास कभी इज्जत ही हुआ करती थी। उसी को ओढ़ता बिछता था वो। उस की ही नुमाइश करता था और फूला फूला फिरता था। मजे की बात शरीफों की ये इकलौती पूंजी भी उससे चुरा ली गई है। अब इज्जत चोरों की होती है। और चोरों की ही होती

है। चोर इतने इज्जतदार है कि चोर और सेठ में भेद मिट चुका। हर बड़ा सेठ बस एक कामयाब चोर है। मजे की बात यह कि ये बात सभी को पता है,सभी को मंजूर है। सब सेठ हो जाना चाहते है। सभी को पता है कि चोर हुए बिना सेठ बना ही नहीं जा सकता , ऐसे मे अब सभी लोग चोर होने के लिए तड़पते है। और चोर होने को बुरा मानने वाले बेवकूफ माने जाते है।

जमाना चोरों का है,सारा जमाना चोर है। चोर होने पर गौरवान्वित है,पर अचरज की बात यह भी कि अब भी कुछ लकीर के फकीर बचे हुए है,डटे हुए है चोर न होने पर। बड़बड़ाने रहते है कि चोरी बुरा काम है। पर अब कोई नहीं पछुता उन्हें। अजीब माना जाता है ऐसे लोगों को। वो अनसुने किए जाते है और उनकी हँसी उड़ाई जाती है। जाहिर है ऐसे लोगों की किस्मत में फकीर बने रहना और फकीर होकर ही मर जाना लिखा है और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है।

अब चारों तरफ चोर है और चोर होना ही मुख्य धारा है। यदि आप दूसरों को शरीफ लगते है,वाकई शरीफ हैं भी तो आप यकीनन गलत रास्ते पर है,और आपको पहली फुरसत मे चोर होकर यह गलती सुधार लेना चाहिए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बाँबे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक

हेमंत पाल

प्रबंध संपादक

रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverere.news@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

विचार

डॉ. ज्योति सिङ्गना

लेखक स्तंभकार हैं।

आज के तकनीक निर्देशित समाज में लगभग सभी सामाजिक संबंध बेमानी से लगने लगे हैं, तकनीक ने मानव जीवन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है संभवतः इसलिए सम्बन्ध कितने भी निकट के क्यों न हों उन पर विश्वास समाप्त हो गया है या कहें कि तकनीक के क्षेत्र में उत्पन्न क्रांति ने सामाजिक सम्बन्धों के समक्ष विश्वास का संकट पैदा कर दिया है। इस दौर में नवजात बच्चियों और किशोरियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं जितनी तेजी से बढ़ रही हैं पहले कभी देखी या सुनी नहीं गयी होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती आई हैं लेकिन 4 दिन और 4 माह की बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि इस सभ्य कहे जाने वाले समाज के मुंह पर तमाचा है परन्तु अफसोस यह है कि इस तमाचे की गूँज किसी को सुनाई नहीं दे रही।

कभी तो लगता है कि महिलाओं के विरुद्ध हुई हिंसा को हिंसा या अपराध की श्रेणी में गिना ही नहीं जाता है इसे उनकी नियति मानकर सामान्य घटना के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि आदिम समाज से लेकर आज के आधुनिक सभ्य समाज तक इन घटनाओं पर कानून तो बहुत बने लेकिन लगाम नहीं लगा सके। आखिर क्यों, यानी कानून बना देने से ही सुधार संभव नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए इस पर सभी क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को विचार करना होगा। बलात्कार की घटनाओं पर विभिन्न नारीवादी विचारकों ने अपना पक्ष रखते हुए माना है कि इसे मात्र एक व्यक्तिगत यौन इच्छा या वासना का अपराध नहीं माना जाना चाहिए। वे इसे पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और महिलाओं पर पुरुष वर्चस्व बनाए रखने के एक हथियार के रूप में देखते हैं। नारीवादी कैथरीन मैककिनन का मानना है कि बलात्कार पुरुष शक्ति और प्रभुत्व का एक चरम रूप है। इसके जरिए महिलाओं को डराकर और नियंत्रित करके रखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज अक्सर बलात्कार के लिए पीड़िता के पहनावे, रहन-सहन या आचरण को दोषी ठहराता है। इस ‘विकिटम-ब्लेमिंग’

(पीड़िता पर दोष मढ़ना) की प्रक्रिया के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज अपराधी को बचाने और महिलाओं को प्रताड़ित करने की व्यवस्था का समर्थन करता आया है।

हाल ही की कुछ घटनाओं में राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर 5 दिन तक 32 लोगों ने गैररेप किया। पश्चिम बंगाल के बुरुईपुरा में 12 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी, उत्तर प्रदेश के बरेली में 11 साल और हरदोई में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और राजस्थान के जोधपुर में 4 माह की नवजात को भी नहीं छोड़ा। क्या इन बच्चियों और नवजात के साथ हुई यौन हिंसा के लिए भी उनके कपड़ों, व्यवहार और चाल-चलन को दोषी ठहरायेगे?

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व की तुलना में महिलाओं को अब अनेक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन इन सबके बावजूद भी उन्हें अपने अस्तित्व और अस्मिता की सुरक्षा का अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। आए दिन सड़को, ट्रेनों, बसों, घरों, खेतों, दफ्तरों में लड़कियां वो सब झेलने को मजबूर होती हैं जो संवैधानिक दृष्टि से भले ही अनैतिक और गैर-कानूनी है लेकिन फिर भी समाज में खुले आम प्रतिदिन होता है मानों उन्हें सामाजिक वैधता प्राप्त हो। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अश्लील फब्कियां, छेछुड़इ, शरीरांगों को गलत तरीके से छूना, दुर्व्यवहार, शारीरिक व मानसिक हिंसा, बलात्कार, अपहरण ऐसे अनेक दुर्व्यवहार लड़कियां प्रतिदिन झेलती हैं। राज्य इन दुर्व्यवहारों के विरुद्ध कानून बना कर या बने हुए कानूनों में संशोधन व परिवर्तन करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ल

वीथिका

लैंगिक हिंसा बनाम सभ्य समाज: जहां हर कोई एक जैसा हो

कभी तो लगता है कि महिलाओं के विरुद्ध हुई हिंसा को हिंसा या अपराध की श्रेणी में गिना ही नहीं जाता है इसे उनकी नियति मानकर सामान्य घटना के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि आदिम समाज से लेकर आज के आधुनिक सभ्य समाज तक इन घटनाओं पर कानून तो बहुत बने लेकिन लगाम नहीं लगा सके। आखिर क्यों, यानी कानून बना देने से ही सुधार संभव नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए इस पर सभी क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को विचार करना होगा। बलात्कार की घटनाओं पर विभिन्न नारीवादी विचारकों ने अपना पक्ष रखते हुए माना है कि इसे मात्र एक व्यक्तिगत यौन इच्छा या वासना का अपराध नहीं माना जाना चाहिए। वे इसे पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और महिलाओं पर पुरुष वर्चस्व बनाए रखने के एक हथियार के रूप में देखते हैं। नारीवादी कैथरीन मैककिनन का मानना है कि बलात्कार पुरुष शक्ति और प्रभुत्व का एक चरम रूप है। इसके जरिए महिलाओं को डराकर और नियंत्रित करके रखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज अक्सर बलात्कार के लिए पीड़िता के पहनावे, रहन-सहन या आचरण को दोषी ठहराता है। इस ‘विकिटम-ब्लेमिंग’ (पीड़िता पर दोष मढ़ना) की प्रक्रिया के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज अपराधी को बचाने और महिलाओं को प्रताड़ित करने की व्यवस्था का समर्थन करता आया है।

झाड़ लेते हैं, समितियां गठित कर दी जाती हैं, जाँच बैठा दी जाती है, नतीजों का कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। मीडिया भी कुछ दिन इन ख़बरों पर अपनी रोटियां सेंकता है फिर उसे कुछ नया मिल जाता है और ऐसी खबरे कहीं दफ़न हो जाती हैं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व दुर्व्यवहार का यह खेल बदस्तूर जारी रहता है।

अधिकांश सेमिनारों, कार्यशालाओं और बौद्धिक चर्चाओं में लड़कियों को कुछ इस तरह की सावधानियां रखने की सलाह दी जाती रही है जैसे चाबियों को हथियार समझकर उसका प्रयोग खुद को बचाने के लिए करे, गाड़ी में बैठने से पहले पिछली सीट पर देख लें, मोबाइल फोन में हेल्प लाइन नंबर रखें, रात में बाहर न निकले, सोते समय सभी खिड़कियां बंद कर लें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, आप अनजाने लोगों से खाने-पीने की कोई वस्तु न ले, मिचं स्प्रे साथ रखें। काम से घर जाते समय अपना रास्ता बदलती रहें, अपने कपड़ों पर ध्यान दें, हाईवे के रेस्ट एरिया का इस्तेमाल न करें, अकेले बाहर न जाकर समूह में बाहर जाएं। सवाल यह है कि यह सावधानियां नवजात और किशोरियों को कैसे सिखाएं या फिर इन समस्याओं का हल केवल यही है कि लड़कियों को ही सावधान रहना होगा। क्या वास्तव में इस सब सावधानियों से यौन हिंसा की घटनाएं रुक जाएंगी।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी देश की स्थिति उस देश की महिलाओं की स्थिति को देखकर ज्ञात की जा सकती है। यदि इस तर्क को सही माना जाए तो फिर कैसे हम दावा कर सकते हैं कि हम देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जिस देश की आधी आबादी प्रतिदिन बलात्कार, हिंसा, यौन शोषण,

तेजाब हमला, दहेज हत्या जैसी घटनाओं का दंश झेलती हो उस देश की स्थिति क्या होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने या महिला सशक्तीकरण का उद्घोष करने से ही अगर महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाया जा सकता तो अब तक आ चुका होता। एक लेखिका ने लिखा भी है दरअसल सवाल यहाँ महिला सशक्तीकरण का है ही नहीं, उन्हें मजबूत या सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे तो पहले से ही मजबूत हैं। जरूरत है दुनिया द्वारा महिलाओं की ताकत को देखने के नजरिए को बदलने की। सच ही तो है अगर पुरुष समाज महिलाओं को देखने का नजरिया बदल ले तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। एक इंसान (पुरुष) को दूसरे इंसान (महिला) के जीवन को निर्धारित करने या निर्देशित करने का अधिकार किससे दिया।

लेखिका ग्लोरिया स्टीनम लिखती हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने शरीर पर अधिकार लोकतंत्र की स्थापना का पहला कदम है और इस आधार पर महिलाएं विशेष रूप से वे जो नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर अवमूल्यित हैं, अभी भी अंतरंग तानाशाही के अधीन हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बलात्कार को सामूहिक आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि आतंकवाद में भी भय उत्पन्न करके दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और बलात्कार में भी महिला व्यवहार को नियंत्रित करना, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, और उन्हें शक्तिहीन साबित करना शामिल होता है। पहले के समय में अधिकांशतः बलात्कार की घटनाओं के लिए अपरिचित/अजनबी जिम्मेदार होता था लेकिन आज तो

परिवार का कोई भी सदस्य पति, देवर, पिता, भाई, दादा, नाना, मामा, चाचा और मित्र इन घटनाओं में संलग्न देखा जा सकता है। यह भी एक तथ्य है कि कुछ पूर्वाग्रह बलात्कार की संस्कृति को वैधता प्रदान करते हैं जैसे लड़के तो लड़के ही होते हैं, लड़की का रात को अकेले निकलना, छोटे कपड़े पहनना, सबसे हँसकर बात करना, पब में जाकर नशा करना, महिलाओं की न का मतलब ही होना इत्यादि। यानी लड़कियों के सोचने, बोलने, पहनने और चलने के तरीको में बलात्कार की संस्कृति अंतर्निहित है।

नारीवादी ऑर्दि लॉर्डें लिखती हैं कि मैं उन महिलाओं के लिए लिखती हूँ जो बोल नहीं पातीं, जिनके पास आवाज नहीं है क्योंकि वे बहुत डरी हुई थीं, क्योंकि हमें डर को खुद से ज्यादा सम्मान देना सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि चुप्पी हमें बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पुरुषों को शिक्षित करें। आज भी महिलाओं से यही अपेक्षा की जाती है कि वे पुरुषों की अज्ञानता की खाई को पाटकर उन्हें हमारे अस्तित्व और हमारी जरूरतों के बारे में शिक्षित करें। एक अन्य नारीवादी रूथ बेडर गिन्सबर्ग का मानना है कि औरतों को असली बराबरी तभी मिलेगी जब मर्द उनके साथ अगली पीढ़ी को पालने की जिम्मेदारी शेयर करेंगे। एक लैंगिक समानता आधारित समाज वह होगा जहां ‘जेंडर’ शब्द प्रयुक्त न हो, जहां हर कोई जैसा है वैसा रह सके। इसलिए जरूरत है कि न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए।

भाषा की राजनीति और राजनीति की भाषा

चिंतन

विवेक रंजन श्रीवास्तव

शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द केवल ध्वनि नहीं रहे, वे मनुष्य की नियति लिखने लगे। सत्ता ने तलवार से पहले शब्दों पर अधिकार करना सीखा, क्योंकि तलवार शरीर को घायल करती है, शब्द चेतना को। इसलिए जहाँ भी राजनीति जन्म लेती है, वहाँ भाषा उसके सबसे विश्वसनीय सेनापति की तरह खड़ी दिखाई देती है। और जहाँ भाषा अपनी सहजता खो देती है, वहाँ समझ लेना चाहिए कि राजनीति ने उसकी ँगुली थाम कर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। भाषा किसी वृक्ष की तरह होती है। उसकी जड़ें लोक में होती हैं, तना संस्कृति में और शाखाएँ भविष्य की ओर फैलती हैं। राजनीति उस वृक्ष पर अपने झंडे बाँध देना चाहती है। वह चाहती है कि हर पत्ता उसकी विचारधारा की दिशा में हिले, हर फूल उसकी विजय का रंग धारण करे। किंतु भाषा का स्वभाव हवा जैसा होता है। उसे बाँधा नहीं जा सकता। वह नदी की भाँति,अंततः उसी दिशा में बहती है जहाँ मनुष्य की संस बची रहती है, जहाँ प्रवाह के लिए बाँधित वैचारिक तथा भाषाई विस्तार की लोक व्यवहार की, उपयोगिता और संप्रेषण की संभावना की गहराई होती है।

राजनीति का पहला कौशल शब्दों के अर्थ बदलना है। वह पराजय को रणनीति, समझौते को दूरदर्शिता, विरोध को षड्यंत्र और प्रचार को जनमत

स्मृति शेष

आदित्य दुबे

लेखक वेबसाइट ई अंतर्भव के प्रबंध संचालक हैं।

भारत में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर की चर्चा हो तो अधिकांश लोगों की पहली पसंद कपिल देव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में यही प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर जैक्स कैलिस होगा। इंग्लैंड की कई पीढ़ियाँ आज भी इयान बॉथम को सर्वोच्च मानती हैं। न्यूजीलैंड में रिचर्ड हैडली, पाकिस्तान में इमरान खान और बांग्लादेश में शाकिब अल हसन के पक्ष में भी गहरी भावनाएँ हैं। हर देश को अपने महानायक पर गर्व करने का अधिकार है।

लेकिन जब चर्चा राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर क्रिकेट के पूरे इतिहास की होने लगे, तब एक नाम लगभग निर्विवाद रूप से सामने आता है—सर गारफील्ड ‘गैरी’ सोबर्स। उनके निधन के साथ केवल वेस्ट इंडीज ने अपना महानायक ही नहीं खोया है, बल्कि क्रिकेट ने वह कसौटी खो दी, जिस पर पिछले छह दशकों से हर महान ऑलराउंडर को परखा जाता रहा। 89 वर्ष की आयु में उनका जाना केवल एक खिलाड़ी का निधन नहीं, बल्कि क्रिकेट के एक ऐसे युग का अवसान है जिसकी प्रतिध्वनि आने वाली पीढ़ियाँ भी सुनती रहेंगी।

सोबर्स केवल आँकड़ों का दसरा नाम नहीं थे; वे उस दुर्लभ क्रिकेटीय कल्पना का साकार रूप थे जिसमें एक अकेला खिलाड़ी मैच का पूरा स्वरूप बदल सकता है। बाएँ हाथ के बल्लेबाज के रूप में वे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के सामने भी सहजता और आक्रामकता का

कहने से भी नहीं हिचकती है। धीरे-धीरे शब्द अपने पुराने वस्त्र उतार देते हैं और नए अर्थों का परिधान पहन लेते हैं। शब्दकोश मौन रहता है, पर समाज का मानस बदल जाता है। यही राजनीति की सबसे सूक्ष्म विजय होती है। जब भाषा सच नहीं बोलती, बल्कि सच का अभिनय करने लगती है।

चुनाव का मौसम वस्तुतः भाषा का सबसे बड़ा उत्सव नहीं, उसकी सबसे कठिन परीक्षा होता है। भाषा और क्षेत्रीयता की भावनाओं को हथियार बनाना राजनीति जानती है। विपक्ष के प्रति भेदे शब्द, फूलों की वर्षा की तरह बरसाये जाते हैं। किंतु उनके भीतर जब तक काँटों का अनुशासन छिपा रहता है,वे लोक मर्यादित भाषा में रहे आते हैं। वादे कविता की तरह सुनाई देते हैं, आरोप व्यंग्य की तरह और घोषणाएँ भविष्यवाणी की तरह। जनता हर बार शब्दों की चमक में अपना कल खोजती है, जबकि राजनीति जानती है कि मतदाता की स्मृति क्षणिक होती है। इसलिए वह हर चुनाव में नई भाषा गढ़ती है, जैसे गिरगिट कामाफ्लाज कर अवसर के अनुरूप नया रंग धारण करता रहता है।

भाषा की अपनी भी राजनीति है। कोई भाषा राजभवनों तक पहुँच जाती है, कोई लोकगीतों में ही जीवन काट देती है। कोई बोली विद्यालय के द्वार पर ही ठिठक जाती है, तो कोई संसद के गलियारों में अधिकांशपूर्वक चलती है। यह केवल व्याकरण का अंतर नहीं, सत्ता के लिए वोटों के वितरण का मानचित्र बनाया जाता है। भाषा का सम्मान दरअसल मनुष्य के सम्मान का दूसरा नाम है। जिस दिन किसी बोली को तुच्छ कहा जाता है, उसी दिन उसके बोलने वाले मनुष्यों की गरिमा भी घायल हो जाती है।

आज यह खेल और भी महीन हो गया है। पहले शब्द भाषणों से निकलते थे, अब वे स्क्रीन से फिसलते हैं। हैशटैग नए नारे हैं, मीम नए व्यंग्य और

ट्रोल नई भीड़ा। सच और झूठ के बीच की दूरी अब शब्दों की नहीं, उनकी गति की हो गई है। जो पहले लोगों के दिलों दिमाग तक पहुँच जाता है, वही अक्सर सत्य मान लिया जाता है। इसलिए राजनीति होड़ करती है। भाषा अब बाज़ार भी है, युद्धभूमि भी और प्रयोगशाला भी, जहाँ हर दिन अर्थों के नए रसायन तैयार किए जा रहे हैं।

फिर भी राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह भाषा का उपयोग तो कर सकती है, स्वाभिम्व नहीं पा सकती। समय सबसे कठोर संपादक है। वह भाषणों की चकाचौंध से चमकीले वाक्य मिटा देता है और केवल वही शब्द बचाकर रखता है जिनमें मनुष्य की करुणा, न्याय और सत्य की धड़कन होती है। इसी कारण इतिहास में असंख्य नारे भूल हो गए, पर कबीर की उलटबाँसियाँ, तुलसी की चौपाइयाँ, प्रेमचंद की भाषा और दिनकर का ओज आज भी जीवित हैं। साहित्य का शब्द संसार सत्ता के लिए नहीं, समय के लिए रचा जाता है।

वास्तव में भाषा और राजनीति का संबंध दर्पण और चेहरे जैसा है। राजनीति जितनी बार अपना चेहरा बदलती है, भाषा उतनी ही बार नया प्रतिबिंब रचती है। किंतु दर्पण की एक ईमानदारी होती है, वह अंततः चेहरा वैसा ही दिखा देता है जैसा वह है। इसलिए किसी राष्ट्र की असली शक्ति उसकी सेनाओं या संसदों से अधिक , उसकी भाषा की नीतिका में निहित होती है। जिस दिन शब्द भय से मुक्त होकर सत्य का उच्चारण करने लगते हैं, उसी दिन लोकतंत्र का वास्तविक सूर्योदय होता है। और जिस दिन भाषा केवल सत्ता की प्रतिध्वनि बनकर रह जाती है, उसी दिन सभ्यता का सांध्यकाल आरंभ हो जाता है। इसलिए साहित्यकार की समाज के प्रति जवाबदारी बहुत ज्यादा होती है।भाषा की राजनीति के गंदे खेल से बचाना केवल व्याकरण को बचाना नहीं, मनुष्य की स्वतंत्र आत्मा को बचाना है।

संपूर्ण क्रिकेटर गैरी सोबर्स का अवसान

सोबर्स केवल आँकड़ों का दूसरा नाम नहीं थे; वे उस दुर्लभ क्रिकेटीय कल्पना के साकार रूप थे जिसमें एक अकेला खिलाड़ी मैच का पूरा स्वरूप बदल सकता है। बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ के रूप में वे दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज़ों के सामने भी सहजता और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन बनाए रखते थे। वही खिलाड़ी नई गेंद से तेज़–मध्यम गेंदबाज़ी कर सकता था, जरूरत पड़ने पर बाएँ हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी डाल सकता था और चाइनामैन भी। स्लिप में खड़े हों तो कैच ऐसे पकड़ते मानो गेंद पहले से उनकी हथेलियों का रास्ता जानती हो।

अद्भुत संतुलन बनाए रखते थे। वही खिलाड़ी नई गेंद से तेज़-मध्यम गेंदबाज़ी कर सकता था, जरूरत पड़ने पर बाएँ हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी डाल सकता था और चाइनामैन भी। स्लिप में खड़े हों तो कैच ऐसे पकड़ते मानो गेंद पहले से उनकी हथेलियों का रास्ता जानती हो।

आज क्रिकेट में ‘डी-शायमेशनल प्लेयर’ की चर्चा होती है, लेकिन सोबर्स उस परिभाषा के भी आगे थे। वे केवल बहुआयामी नहीं, बल्कि लगभग असीम संभावनाओं वाले क्रिकेटर थे। उन्हें किसी एक भूमिका, किसी एक शैली या किसी एक विशेषता में बाँधना संभव ही नहीं था।

यही कारण है कि कपिल देव, जैक्स कैलिस, इयान बॉथम, इमरान खान या बेन स्टोक्स जैसे महान खिलाड़ियों की चर्चा अंततः सोबर्स की कसौटी तक पहुँच जाती है। कपिल ने भारत को पहला विश्व कप दिलाया। कैलिस ने अद्भुत निरंतरता का मानक स्थापित किया। बॉथम ने एशेज की सबसे यादगार कहानियाँ लिखीं। इमरान खान ने नेतृत्व, व्यक्तित्व और प्रदर्शन–तीनों से इतिहास रचा। इन सबकी उपलब्धियाँ अपने-अपने संदर्भ में असाधारण हैं, लेकिन सोबर्स का

व्यक्तित्व इन सभी गुणों का संगम था। वे विश्वस्तरीय बल्लेबाज थे, प्रभावशाली गेंदबाज थे और असाधारण क्षेत्ररक्षक भी। इसलिए क्रिकेट इतिहास ने उन्हें केवल महान ऑलराउंडर नहीं, बल्कि ‘सबसे संपूर्ण क्रिकेटर’ का दर्जा दिया।

उनका 365* का विश्व रिकॉर्ड, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में छह छकों का ऐतिहासिक कारनामा और लगभग दो दशकों तक वेस्ट इंडीज के लिए निभाई गई उनकी केंद्रीय भूमिका आज भी किंवदंती का हिस्सा हैं। लेकिन उनकी महानता इन उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी।

सोबर्स का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने क्रिकेट की संभावनाओं का दायरा बढ़ाया। उन्होंने सिद्ध किया कि किसी खिलाड़ी को किसी एक सॉचे में सीमित नहीं किया जा सकता है। वे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते थे और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आज, जब क्रिकेट विशेषज्ञता का खेल बन चुका है–जहाँ बल्लेबाज, गेंदबाज और फिनिशर अलग-अलग भूमिकाओं में बंटे जाते हैं–सोबर्स की विरासत और भी विराट दिखाई देती है। वे उस दौर में भी आधुनिक थे,

जब आधुनिक क्रिकेट की अवधारणा अभी जन्म ही ले रही थी।

वेस्ट इंडीज क्रिकेट के स्वर्णिम युग की बुनियाद भी काफी हद तक सोबर्स की पीढ़ी ने ही रखी। बाद में क्लाइव लॉयड और विवियन रिचर्ड्स की टीमों ने विश्व क्रिकेट पर जो दबदबा कायम किया, उसकी नींव पहले ही तैयार हो चुकी थी। कैरेबियाई क्रिकेट को आत्मविश्वास, सम्मान और वैश्विक पहचान दिलाने में सोबर्स का योगदान किसी विश्व कप विजय से कम नहीं आँका जा सकता। वे केवल महान खिलाड़ी नहीं थे; वे उस सांस्कृतिक आत्मविश्वास के प्रतीक थे जिसने छोटे-छोटे कैरेबियाई द्वीपों को क्रिकेट की महाशक्ति बना दिया।

आज सोशल मीडिया के दौर में महानता की बहसें अक्सर आँकड़ों तक सिमट जाती हैं। बल्लेबाज़ी औसत, स्ट्राइक रेट, विकेट, कैच और रिकॉर्ड–सब कुछ तुलना का आधार बन जाता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी आँकड़ों से कहीं बड़े होते हैं। सोबर्स उन्हीं विरले खिलाड़ियों में थे। जिन्होंने उन्हें खेलेते देखा, उनका कहना था कि उन्हें समझने के लिए स्कोरकार्ड पर्याप्त नहीं; आँखों की गवाही

समझना है कि नशे की समस्या का प्रभावी समाधान कानून और उपचार–दोनों के संतुलित प्रयासों से ही संभव है। माता-पिता, शिक्षक और समाज की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ खुला संवाद, भावनात्मक सहयोग, सकारात्मक वातावरण और वैज्ञानिक जानकारी उन्हें नशे से दूर रखने के सबसे प्रभावी उपाय हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य तथा नशामुक्ति पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है, तो उसे शर्म या भय के कारण उपचार से दूर नहीं रहना चाहिए। आज दवाओं, मनोचिकित्सकीय परामर्श, मनोचिकित्सा और पुनर्वास की प्रभावी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। समय पर उपचार मिलने से अधिकांश लोग स्वस्थ और सामान्य जीवन में वापस लौट सकते हैं।

अंततः ‘नशे से दूरी है ज़रूरी’ केवल मध्यप्रदेश पुलिस का अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार, विद्यालय, चिकित्सक और नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। जब कानून, समाज और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलकर कार्य करेंगी, तभी नशामुक्त, सुरक्षित और स्वस्थ समाज का लक्ष्य वास्तव में प्राप्त किया जा सकेगा।

नशे से दूरी है जरूरी: मानसिक स्वास्थ्य का भी अभियान

चाहिए। वे क्रिकेट केवल खेलते नहीं थे, उसे कला में रूपांतरित कर देते थे।

यही कारण है कि उनके समकालीनों से लेकर आधुनिक युग के दिग्गजों तक, लगभग सभी ने उन्हें क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माना। उनके निधन पर दुनिया भर के क्रिकेट बोर्डों, पूर्व खिलाड़ियों और प्रशंसकों द्वारा व्यक्त शोक इस सार्वभौमिक सम्मान का प्रमाण है। सर गैरी सोबर्स के जाने से क्रिकेट अनाथ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी विरासत अमर रहेगी। लेकिन यह खल निस्संदेह थोड़ा अकेला हो गया है।

आने वाले वर्षों में नए ऑलराउंडर उभरेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे और नई पीढ़ियाँ अपने-अपने नायकों को चुनेंगी। भारत फिर कपिल देव को याद करेगा, दक्षिण अफ्रीका कैलिस को और इंग्लैंड बॉथम को। यह स्वाभाविक भी है। किंतु जब प्रश्न यह होगा कि क्रिकेट ने अब तक का सबसे संपूर्ण खिलाड़ी किसे देखा, तो इतिहास शायद फिर उसी नाम पर ठहर जाएगा–सर गैरी सोबर्स।

कुछ महान खिलाड़ी अपने देश के होते हैं, कुछ अपने युग के। लेकिन कुछ विरले ऐसे होते हैं जो पूरे खेल की साझा धरोहर बन जाते हैं। सर गैरी सोबर्स उसी विरल परंपरा के सबसे उज्ज्वल प्रतीकों में थे।

क्रिकेट का वह ऋषि अब मैदान पर नहीं उतरेगा, लेकिन जब भी कोई युवा खिलाड़ी बल्ले, गेंद और क्षेत्ररक्षण–तीनों में उत्कृष्ट बनने का सपना देखेगा, वह अनजाने ही सोबर्स की विरासत का अनुसरण कर रहा होगा। किसी खिलाड़ी की अमरता शायद इससे बड़ी नहीं हो सकती।

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक स्तंभकार हैं।



आखिरकार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 साल से चली आ रही पेंशनरों की मांग को मान लिया और उन्होंने पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति लेने की प्रचलित परंपरा को खत्म कर दिया। अब मध्यप्रदेश के और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को राज्य शासन द्वारा बढ़ाई गई मंहगाई राहत तुरंत मिल सकेगी। इस निर्णय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की भी अहम भूमिका है।

मध्यप्रदेश के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी और छत्तीसगढ़ राज्य के

सिद्ध महाराज के पास गौशाला की भूमि अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर एसडीएम डॉ. बबीता राठौर से मुलाकात की

सोहागपुर। सोहागपुर ही नहीं क्षेत्र के विख्यात सिद्ध महाराज के समीप सिटीया गोहना गौशाला की लगभग 16 एकड़ शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण एवं मजार निर्माण के संबंध में सकल हिंदू समाज एवं नागरिक संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर से मुलाकात की इस प्रतिनिधिमंडल में समाजसेवी कृष्णा पालीवाल, पत्रकार संघ अध्यक्ष पवनसिंह चौहान, पत्रकार अमित बिस्मैरे, वकील शिवकुमार पटेल, समाजसेवी विशाल गोिलानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रतेन्द्र सिंह राजपूत, पूर्व जिला बजरंग दल रूपेश खुबंशी, पूर्व बजरंग दल जिला



सुस्था संयोजक आशीष पुरोहित आदि शामिल थे।प्रतिनिधिमंडल ने अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर से आग्रह किया कि क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्ध महाराज के समीप गौशाला की करीबन 16 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया। इस अतिक्रमण की संपूर्ण शासकीय भूमि का राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकन कराया जाए। सीमांकन के उपरांत यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत दृटकर पूरी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शासकीय भूमि का संरक्षण तथा उसका वैधानिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना जनहित एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण विषय है। प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधि एवं वकील शिवकुमार पटेल ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्चस्त किया है कि गो शाला की संपूर्ण 16 एकड़ भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर परीक्षण एवं सीमांकन कराया जाएगा।।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का पुतला दहन, सांसद दर्शनसिंह आदि के विरुद्ध नारेबाजी

सोहागपुर। किसान कांग्रेस का शत-प्रतिशत मूंग खरीदी को लेकर ‘गांव-गांव पुतला दहन’ आंदोलन जारी है। इसी तारतम्य में आज सोहागपुर के मुख्य बाजार नर्मदापुरम पिपरिया राज्य मार्ग 22 पर शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसान कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के तत्वावधान में हो रहे इस आन्दोलन को सभी कांग्रेस जनों ने एकत्रित होकर किसानों के साथ केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले का दहन किया गया। पुतला दहन के अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते करते यकायक क्षेत्रीय सांसद दर्शनसिंह के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इसी बीच पुतला दहन के समय पुलिसकर्मियों ने पुतले पर पानी डालने एवं पुतला छीनने की कोशिश असफल कोशिश की गई। किसान कांग्रेस के तत्वावधान में चलाए जा रहे निरंतर ‘गांव-गांव पुतला दहन कार्यक्रम’ के तहत क्षेत्र के किसान अपनी मांगों शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर पूरी तरह अडिग नजर आ रहे हैं। उक्त आन्दोलन प्रदर्शन वरिष्ठ किसान नेता पुष्पाजसिंह पटेल एवं जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बाबू चौधरी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे हैं। पुतला दहन के अवसर पर संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की वर्तमान नीतियां किसान विरोधी है।यह सरकार किसानों के हितों की निरंतर अन्वेषी कर रही है। मूंग को शत-प्रतिशत मूंग न खरीदे जाने से क्षेत्र का अन्नदाता आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार किसानों की शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को स्वीकार नहीं करती तब तक चरणबद्ध आंदोलन तथा गांव-गांव में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान आदि के पुतला दहन का सिलसिला जारी रहेगा।

धार में 1.90 करोड़ खर्च कर लगाए गए पौधे सूखे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत काटे गए थे हजारों पेड़, भरपाई के लिए किया गया था प्लांटेशन



धार (नप्र)। धार जिले के सरदारपुर वन परिक्षेत्र की कौद बीट के ग्राम शेरगढ़ में मेट्रो रेल परियोजना के तहत काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए किया गया वृक्षारोपण सवालों के घेरे में है।

वन विभाग ने करीब तीन महीने पहले 30.178 हेक्टेयर क्षेत्र में 30,178 पौधे लगाए थे, लेकिन अब इनमें से हजारों

पौधे सूख चुके हैं। कई जगह पौधों का नामीनशान तक नहीं है। जहां पौधे लगाए गए थे, वहां अब सिर्फ सूखे डंठल दिखाई दे रहे हैं। इस वृक्षारोपण पर करीब 1 करोड़ 91 लाख 77 हजार रुपए खर्च किए गए थे। इसका उद्देश्य मेट्रो रेल परियोजना में कटे पेड़ों की भरपाई करना और क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना था। लेकिन मौजूदा स्थिति योजना

वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा संयुक्त रूप से जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान में प्रचलित पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया तथा प्रशासनिक सुगमता एवं पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए हैं-

(क) मंहगाई राहत घोषित करने हेतु दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। (ख) पेंशनरों को देय पेंशन राहत में वृद्धि हेतु विधायी संशोधन के स्थान पर दोनों राज्यों द्वारा सीधे कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। (ग) राज्यों के आदेश से वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार के संबंध में मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

शासन को सूचना हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। (घ) कोई भी राज्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मंहगाई राहत की दरों से अधिक दर घोषित नहीं करेगा। उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील रहेगा। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा उक्त आदेश 17 जुलाई 2026 को जारी किया गया। इस आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे। पहले दोनों राज्य सरकार जब भी अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता घोषित करती थी तो आदेश के दिनांक से कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का लाभ मिल जाया करता था। किन्तु पेंशनरों की मंहगाई राहत की दरों में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगती थी। इसमें कई महीनों का समय लग जाता था। और जब भी छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त होती थी, उस दिनांक से मध्यप्रदेश सरकार मंहगाई राहत का

आदेश जारी करती थी। इसमें होता यह था कि जब भी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलता था तो उसके कई महीनों बाद पेंशनरों को मंहगाई राहत मिल पाती थी। इससे पेंशनरों का काफी आर्थिक नुकसान होता था। यह नाईसाफी पिछले कई सालों से चल रही थी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य सरकारों ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को समाप्त या विलोपित नहीं किया है। कोई भी राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम को समाप्त या विलोपित नहीं कर सकती। यह अधिकारकेन्द्र सरकार को ही है। इसलिए दोनों राज्य सरकारों ने बीच का रास्ता निकाला और उक्त आदेश के (ख) के द्वारा पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि हेतु विधायी संशोधन के स्थान पर दोनों राज्यों द्वारा

सीधे कार्यकारी आदेश जारी किए गए।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की सदाशयता से दोनों राज्यों के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। इससे पेंशनरों की और पेंशनर संगठनों की 25 साल से चली आ रही मांग को दोनों राज्य सरकारों ने मानकर पेंशनरों को मंहगाई राहत देने का आखिरकार रास्ता निकाल ही लिया। यदि दोनों राज्य सरकारें पेंशनरों के हित में मध्यप्रदेश पुनर्गठन 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजती तो इसमें कितना समय लगता? इसकी कोई ग्यारसी नहीं थी। इसलिए बहुत सोच समझकर दोनों राज्य सरकारों ने बीच का रास्ता निकालकर पेंशनरों के लिए सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए दोनों राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों को साधुवाद!

भोपाल की कंपनी को मिला बैतूल -इटारसी के बीच फोरलेन निर्माण का ठेका

बैतूल। बैतूल-इटारसी फोरलेन के बीच बचे 21 किमी सड़क निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सिर्फ हाईकोर्ट से स्टे हटाने की देरी है। जैसे ही स्टे हटेगा, सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जायेगा। फिलहाल सड़क निर्माण को लेकर टैंडर भी हो चुके है। एनएचआई द्वारा भोपाल की एक कंपनी को टेंडर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 21 किमी सड़क निर्माण के इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इधर टैंडर प्रक्रिया के बाद कंपनी द्वारा प्लांट लगाने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। वन क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में वन जीवों की आवाजाही के लिए जगह-जगह अंडरपास और ओवरपास बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगभग दो से ढाई साल की अवधि में उक्त प्रोजेक्ट पूर्ण किया जाएगा। बरेठा सहित धार और केसला वन क्षेत्र में फोरलेन सड़क निर्माण होने से भोपाल तक का सफर आसान हो जाएगा। बता दें कि बैतूल जिले के बरेठा सहित नर्मदापुरम के धार और केसला में आने वाली इस सड़क के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक लगी थी। जिसके कारण यह सड़क नहीं बन पाई और इटारसी-बैतूल के माध्यम लगभग 21 किलोमीटर का भाग शेष रह गया था। लेकिन फोरलेन बनाने के लिए एनएचआई ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप प्लान बना लिया है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड एवं केंद्र सरकार से सभी जरुरी अनुमतियां भी प्राप्त कर ली है। अब हाईकोर्ट का स्टे औपचारिक रूप से हटते ही यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

आसानी हो जायेगा नागपुर-भोपाल का सफर- नागपुर-भोपाल जैसी दो बड़े महानगरों को जोड़ने वाले नेशनल हाइवे पर अब तक अवरोध बैतूल जिले में स्थित बरेठा घाट बचा है। भोपाल और नागपुर के बीच आवागमन को सुगम और तेज करने के लिए वैसे तो कई साल पहले बैतूल से नागपुर और बैतूल से भोपाल के लिए फोरलेन

युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है, भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं : विधायक विजयपालसिंह

सोहागपुर। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उक्त उद्गार कार्यक्रम मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने भारतीय जनता पार्टी मंडल सोहागपुर के तत्वावधान में सोहागपुर विधायक कार्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम एवं नव मतदाता संवाद के अवसर पर कहे। इस अवसर नगर परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुरेश पटेल, वरिष्ठ वकील जेपी माहेश्वरी,संतोष तिवारी, अंजनी पटेल मुख्य रूप से उपस्थित थे । क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने आगे कहा कि भाजपा केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करती है। बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के संकल्प के साथ कार्य करती है। जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। आपने अपने उद्बोधन में बड़े ही मार्के की बात कही कि यदि कोई उन पर भ्रष्टाचार



का एक भी प्रमाण सिद्ध कर दे तो वे उसी दिन सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। आपने अपने विस्तृत सारगर्भित उद्बोधन में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोहागपुर को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की सौगात मिल चुकी है तथा आने वाले समय में मुहारा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग एक लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

आपने युवाओं से उद्योग लगाने का आह्वान किया । ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े। आपने अंत में नव मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए मतदान करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर की वक्ताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यालयों के संकल्प, युवाओं के भविष्य, रोजगार, शिक्षा, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर सारगर्भित विस्तृत संवाद किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज, जिला भाजयुमो अभिनव पालीवाल, पार्षद रविशंकर उडके, पार्षद गौरव पालीवाल, पार्षद आशीष विश्वकर्मा, भाजपा नेता केशव जाजू शोभापुर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन अनिल गैरिया ने किया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले से 260 श्रद्धालु हरिद्वार-ऋषिकेश रवाना

बैतूल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के लगभग 260 श्रद्धालुओं को रविवार को हरिद्वार-ऋषिकेश की चार दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उडके ने बुजुर्ग यात्रियों का पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया तथा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, अपर कलेक्टर वंदना जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदिरा महतो सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री उडके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के सम्मान और उनकी आस्था को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जीवनभर परिवार और समाज की सेवा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का अवसर देना सरकार की संवेदनशील सोच का परिचायक है। उन्होंने यात्रियों से यात्रा के दौरान आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने, देश की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने तथा प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी यात्रियों के सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यह हरिद्वार-ऋषिकेश यात्रा 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। यात्रा के लिए बैतूल जिले से कुल 260 यात्रियों का चयन किया गया है।

बैंक राष्ट्रीयकरण की 57वीं वर्षगांठ पर एआईबीओसी मप्र इकाई का ‘हरित संकल्प’

100 से अधिक पौधों का रोपण, विभिन्न बैंकों के सैकड़ों अधिकारियों ने एकजुट होकर दिया पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश

भोपाल। बैंक राष्ट्रीयकरण की 57वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC), मध्यप्रदेश इकाई द्वारा जम्बूरी मैदान, BHEL, भोपाल में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैंकिंग इतिहास के इस महत्वपूर्ण अवसर को सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए 100 से अधिक पौधों का रोपण किया गया तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया गया।

कार्यक्रम की विशेषता रही कि AIBOC के विभिन्न घटक संगठनों से जुड़े भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के सैकड़ों अधिकारी साथी एक मंच पर एकजुट हुए। बैंकिंग बिगडारी की इस व्यापक सहभागिता ने संगठनात्मक एकता, सामाजिक प्रतिबद्धता और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। AIBOC के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ‘बैंक राष्ट्रीयकरण केवल बैंकों के

स्वामित्व में परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारतीय बैंकिंग को जेनो-मुक्ती बनाने वाली ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक पहल थी। इसने किसान, श्रमिक, छोटे उद्यमी और समाज के वंचित वर्गों तक संस्थागत बैंकिंग की पहुँच का विस्तार किया। आज उसी जनकल्याण की भावना को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना इस ऐतिहासिक अवसर की सार्थक अभिव्यक्ति है।’

AIBOC मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुबिन सिन्हा ने कहा, ‘राष्ट्रनिर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी रही है। आज विभिन्न बैंकों के सैकड़ों अधिकारियों का पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होना दर्शाता है कि बैंक अधिकारी अपने व्यावसायिक दायित्वों के साथ समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी प्रतिबद्धता से निभा रहे हैं।’

AIBOC मध्यप्रदेश इकाई के सचिव दिनेश झा ने कहा, ‘हमारा उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित एवं विकसित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित विरासत तैयार करना है। आज लगाया गया प्रत्येक पौधा स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य के

प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।’

इस वृहद पौधारोपण अभियान को सुकवस्थित एवं प्रभावी स्वरूप देने में पर्यावरण हितैषी एवं SBI ऑक्सीडियन बैंक के संस्थापक डॉ. फंकु भारती का विशेष सहयोग रहा। उनकी देखरेख एवं मार्गदर्शन में पौधों के चयन, व्यवस्थित रोपण तथा उनके भावी संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके निरंतर प्रयासों एवं अनुभव ने इस अभियान को विशेष सार्थकता प्रदान की। कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आम्बरीश नंदा, पंजाब नेशनल बैंक के जनरल सेक्रेटरी निर्भय सिंह, यूनियन बैंक ऑफिसर्स यूनियन पंडितार तथा केनरा बैंक के मनीष चतुर्वेदी सहित विभिन्न घटक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की।



संक्षिप्त समाचार

मानोरा मेले में परिवहन विभाग की सघन जांच

8 वाहनों पर चालानी कार्रवाई



विदिशा, (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशों के पालन में जिला परिवहन विभाग द्वारा मानोरा मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानोरा रोड पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरिजेश वर्मा ने किया। जांच अभियान के दौरान मानोरा मेले की ओर जा रहे यात्री वाहनों एवं अन्य वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित 8 वाहन पाए गए, जिनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 76,700 रुपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरिजेश वर्मा ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की अधिक आवाजाही को देखते हुए यात्री वाहनों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। वाहन चालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने, सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, फिटनेस एवं परमिट नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक वाहन संचालन के निर्देश दिए गए।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर शिविर लगाकर किया गया 724 बच्चों का टीकाकरण



सीहोर, (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं एवं अनेक स्थानों पर प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत शिविर लगाकर टीकाकरण के साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत जिले में 17 जुलाई को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 497 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 227 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 108 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि दीदियों को दिया गया प्रशिक्षण



सीहोर, (निप्र)। एसआरएलएम एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा स्थानीय बीजों के संरक्षण, उनकी देखरेख तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीहोर में कृषि दीदियों का एक दिवसीय सामर्थ्य निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय बीजों के संरक्षण, बीज बैंक की अवधारणा, बीज उपचार, प्राकृतिक खेती की तकनीकों तथा गांव स्तर पर किसानों के बीच इन नवाचारों के प्रसार पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि दीदियों को स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक खेती के प्रभावी संवाहक के रूप में सशक्त बनाना था, ताकि वे किसानों को स्थानीय बीजों के संरक्षण, जैविक उपायों एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक कर सकें।

अवैध शराब के विरुद्ध राजस्व, पुलिस एवं आबकारी संयुक्त रूप से करें प्रभावी कार्रवाई : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

■ आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रतिदिन सुबह नाश्ता एवं थर्ड मील उपलब्ध कराने के लिए निर्देश

बैतूल, (निप्र)। घोड़ाडोंगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत चोपना में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने चोपना सहित घोड़ाडोंगरी के विभिन्न ग्रामों के लिए नियुक्त जिला अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की समीक्षा की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं की जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉ सोनवणे ने नशे की समस्या पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर सुबह का नाश्ता अनिवार्य रूप से मिले तथा थर्ड मील का वितरण भी नियमित



रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को ई-टोकन जनरेट कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए प्रत्येक गांव में 8 से 10 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर इस कार्य से जोड़ा जाए, ताकि किसानों को

स्थानीय स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक में ग्रामवार प्राप्त समस्याओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने ग्राम रामपुर में सोनभद्र नदी पर बैराज निर्माण, बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को पुनः चालू कराने, बीएसएनएल नेटवर्क की समस्या तथा जर्जर आंगनवाड़ी भवन की छत के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत गोलई बुजुर्ग में आंगनवाड़ी



स्कूल के अतिरिक्त कक्ष निर्माण में देरी पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को नोटिस

बैतूल, (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शुक्रवार को घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम हीरापुर का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान ग्रामीण सविता सोनी ने आवास एवं आजीविका से जुड़ी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता की जांच कर लाभ दिलाते तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम में संचालित किए जाने वाले रेशम केंद्र के संचालन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम में नल-जल योजना बंद होने की शिकायत पर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल

टीम भेजकर जल स्रोत एवं पाइपलाइन की जांच कर शीघ्र समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा रखी गई मार्ग निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान सहित अन्य समस्याओं पर भी संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत भवन के नियमित एवं व्यवस्थित संचालन के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। प्राथमिक शाला का निरीक्षण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण में देरी पर कार्रवाई कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने ग्राम हीरापुर की प्राथमिक शाला का निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर दर्ज छात्र संख्या की जानकारी ली तथा शिक्षकों को पर्याप्त रशनी सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए शाला का सुव्यवस्थित संचालन करने और नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में निर्माणधीन अतिरिक्त कक्ष का भी अवलोकन किया।

जल जमाव वाले स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था करें नगरीय निकाय

खाली प्लाटों पर जल जमाव न हो

हरदा, (निप्र)। हंडिया नर्मदा घाट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिये की जाए सतत निगरानीघंटा घर क्षेत्र होगा अतिक्रमण मुक्त, सुधरेगी यातायात व्यवस्थाजनर भवनों में स्कूल संचालित न होरिंगरोड निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएसड़कों से पानी के की व्यवस्था करें पीडब्ल्यूडी - कलेक्टरहरदा 17 जुलाई 2026/ कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के दृष्टिगत खाली पड़े प्लाटों में जल जमाव न होने देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी नगरीय क्षेत्रों में जल जमाव वाले स्थानों पर जल निकासी की समूचित व्यवस्थाएं करने के लिये भी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है।

जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया कि खाली पड़े जिन प्लाटों में जल भराव हो रहा है और मच्छर पनप रहे हैं, उन प्लाटों के मालिकों को नगर पालिका द्वारा नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पाबंद किया है कि जहां जल भराव हो रहा है, वहां मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये फागिंग एवं अन्य आवश्यक उपाय किये जाएं। बैठक में उन्होने हंडिया नर्मदा घाट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिये सतत निगरानी करने



के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि जो दुकानदार प्लास्टिक फ्री व्यवस्था का उल्लंघन करते है, उन पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जाए। हरदा नगर के घण्टा घर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के भी बैठक में निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि घण्टा घर क्षेत्र की व्यवस्था आमजन के लिये सुगम हो एवं यहां की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि किसी भी सूरत में जर्जर भवनों में स्कूलों का संचालन न हो। कलेक्टर ने कहा कि हरदा नगर के बाहर से प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण के कार्य में आर्वाड होने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसके निर्माण की कार्रवाई शीघ्र प्रारम्भ की जाए। उन्होने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को ताकीद किया कि

सड़कों के निर्माण में पानी के निकास की व्यवस्था जरूर की जाए। कहीं भी सड़कों पर बरसाती पानी का भराव न हो, यह सुनिश्चित करें। बैठक में सड़कों पर बिचरण करने वाले निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन, अपर कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम कुमार, एसडीएम हरदा श्री अशोक डहेरिया, एसडीएम टिम्परनी श्री शैलेन्द्र बड़ोनिया, एसडीएम खिरकिया सुश्री रजनी वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बटकीडोह पंचायत में कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

पानी, सड़क, बिजली और नशे के मुद्दों पर दिए त्वरित कार्यवाही निर्देश



बैतूल, (निप्र)। घोड़ाडोंगरी विकासखंड के भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने ग्राम बटकीडोह के पंचायत भवन में आयोजित जनसंवाद में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने पेयजल, सड़क, बिजली, नशे की समस्या सहित अन्य स्थानीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं समय पर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्राम पंचायत को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के

आधार पर विकास कार्ययोजना का रिवाइज किया जाए, ताकि वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य कराए जा सकें।

विद्यालय आने-जाने में विद्यार्थियों को हो रही कठिनाई का संज्ञान लेते हुए उन्होंने धरमपुर से बटकीडोह तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने पंचायत, विद्यालय, आंगनवाड़ी, मोक्षधाम सहित सभी सार्वजनिक परिसरों में व्यापक स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने तथा लगाए गए पौधों का नियमित

देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल की बेहत व्यवस्था हर हाल में उपलब्ध रहे। जनसंवाद के दौरान कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्रामीणों से राशन वितरण, आंगनवाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन तथा बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार की जानकारी भी ली और संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

ग्रामीणों द्वारा समग्र आईडी में पता संशोधन नहीं होने के कारण विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की समस्या बताते पर उन्होंने ग्राम पंचायत को निर्देश दिए कि ऐसे सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर दो दिनों के भीतर समग्र आईडी अपडेट कराना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम में युवाओं के नशे की लत की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम भेजकर अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने पंचायत में निर्मित टिन शेड की गुणवत्ताविहीन होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित उपयंत्री (सब इंजीनियर) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।



एसडीएम सुश्री रजनी वर्मा ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

हरदा, (निप्र)। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री रजनी वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय खिरकिया में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। एसडीएम सुश्री रजनी वर्मा ने बैठक के दौरान सभी विभागों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने

और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और मंडी से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी तथा मंडी सचिव सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

अमृत भारत स्टेशन योजना तहत पुनर्विकसित विदिशा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ



विदिशा, (निप्र)। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के विदिशा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन

योजना के अंतर्गत आधुनिक स्वरूप में विकसित होकर यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री जी ने किया वर्चुअल उद्घाटन यात्रियों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

जी ने वर्चुअल आज रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। आधुनिक वास्तुशिल्प, अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं तथा दिव्यांगजन अनुकूल अड्योसंरचना से सुसज्जित यह स्टेशन अब क्षेत्र के विकास, पर्यटन एवं आधुनिक भारतीय रेलवे की नई पहचान के रूप में स्थापित होगा।

विदिशा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से केंद्रीय किसान कल्याण तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जुड़े और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित कर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है प्रधानमंत्री जी द्वारा विदिशा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के 75 रेलवे स्टेशनों में 13 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के शामिल है, जिनका उद्घाटन किया गया है। विदिशा नगरी सांस्कृतिक आध्यात्मिकता का केंद्र है। आज अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करोड़ों देशवासियों का भविष्य बदल रहा है। इन

सुंदर और भव्य स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है। भारतीय रेल के बुनियादी ढांचे में तेज गति से क्रांतिकारी बदलाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है। विदिशा रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री रजनीश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य किये जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाना सहित वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। आधुनिक रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि भारत देश आधुनिक ट्रेन प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केवल मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ के कार्यालय रेलवे क्षेत्र में हुए हैं आगे भी कार्य किए जाएंगे। विकास कार्यों में कोई पूर्व कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कार्यक्रम को विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि हमारे विदिशा का सौभाग्य है जो आज प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन की इतनी बड़ी सौगात दे

रहे हैं जहां आधुनिक सुविधाएं मिलने जा रही हैं। उन्होंने विदेशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में किए गए विभिन्न कार्यों को रेखांकित किया।

विदिशा रेलवे स्टेशन के लिए इतनी बड़ी सौगात के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी, मध्यप्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राम मोहन बघेल, श्री महाराज सिंह दांगी, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राकेश जादौन, विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा के अलावा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र काशवाणी, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया, समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, रेलवे एंडीआरएम अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विद्यार्थीगण, जनसमूह एवं रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गईं।

